

मेट्रो का ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट एक पड़ाव पार

माई सिटी रिपोर्टर

लखनऊ। लखनऊ मेट्रो के दूसरे चरण की परियोजना ने एक अहम पड़ाव पार कर लिया है। चारबाग से बसंतकुंज के बीच बनने वाले ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर को नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) ने हरी झंडी दे दी है। मार्च में प्रदेश सरकार ने इस परियोजना को फाइनल कर केंद्र सरकार को भेजा था। अब प्रोजेक्ट के विस्तृत रिपोर्ट यानी डीपीआर को पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड और केंद्रीय कैबिनेट से मंजूर कराया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट की हरी झंडी मिलते ही काम शुरू हो जाएगा।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अपर सचिव की अध्यक्षता में दिल्ली स्थित वाणिज्य भवन में 9 जुलाई को एनपीजी की बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान पोर्टल के

चारबाग से बसंतकुंज के बीच 11.098 किमी में होंगे 12 स्टेशन



जरिये ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के रूट में पड़ने वाली पानी की पाइपलाइन, ट्रांसमिशन व सीवर लाइन के साथ ही रेलवे लाइन, पुरातत्व से संबंधित स्मारक, बस स्टैंड, पुल, फ्लाईओवर आदि पर

5081 करोड़ से पांच साल में बनेगा कॉरिडोर

चारबाग से बसंतकुंज तक ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर की कुल मार्ग लंबाई 11.098 किमी होगी। इसमें चार किमी से अधिक एलिवेटेड ट्रैक होगा, जबकि करीब सात किमी भूमिगत होगा। कॉरिडोर में कुल स्टेशनों की संख्या 12 होगी, जिसमें सात भूमिगत और पांच एलिवेटेड होंगे। इसपर 5081 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है। निर्माण कार्य पांच साल में पूरा होगा।

ये स्टेशन होंगे

चारबाग से बसंतकुंज तक लखनऊ मेट्रो का ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर पुराने लखनऊ के प्रमुख स्थानों अमीनाबाद, चौक को जोड़ने में मदद करेगा। मेट्रो के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने बताया कि ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर को एनपीजी से मंजूरी मिलना एक बड़ी उपलब्धि है। लखनऊ के शहरी परिवहन के साथ ही मौजूदा मेट्रो कॉरिडोर के लिए यह परियोजना बेहद अहम है। इसमें चारबाग, गौतमबुद्ध मार्ग, अमीनाबाद, पांडेयगंज, सिटी रेलवे स्टेशन, मेडिकल चौराहा, चौक भूमिगत स्टेशन होंगे जबकि ठाकुरगंज, बालागंज, सरफराजगंज, मूसाबाग व बसंतकुंज स्टेशन एलिवेटेड होंगे।

चर्चा हुई। इस पोर्टल से स्थलीय परीक्षण से पहले इन सब चीजों की सटीक जानकारी मिल जाती है। इसमें ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर मेट्रो निर्माण में कोई बाधा नहीं पाई गई। बैठक में परियोजना से संबंधित

विभाग जैसे केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास, रक्षा, रेलवे, पर्यावरण एवं वन विभाग, वित्त के प्रतिनिधि शामिल हुए। डीपीआर को पास कराने के लिए एनपीजी की मंजूरी अहम होती है।